डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

DFC News

डीएफसी समाचार

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
WE BELIEVE IN SINCERITY, SPEED & SUCCESS

वर्ष 8, अंक 26 | जनवरी–मार्च, 2017

वर्ष 2016-17 में डीएफसी की प्रगति हुई और तेज़ पहली बार रु.10,000 करोड़ से ज़्यादा पूंजीगत व्यय

डीएफसीसीआईएल के लिए वर्ष 2016–17 अनेक उपलब्धियों से भरा रहा। इस दौरान डीएफसीसीआईएल ने कांट्रैक्ट अवार्ड, भूमि अधिग्रहण, पूंजीगत व्ययों तथा निर्माण, सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

वर्ष 2016–17 कांट्रैक्ट अवार्ड के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। **इस दौरान, दोनों कोरीडोरों को मिलाकर रु. 11,643 करोड़ के कांट्रैक्ट अवार्ड किए गए। इस प्रकार अब तक अवार्ड किए गए कांट्रैक्टों का कुल मूल्य (cumulative value) रु. 48,954 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो डीएफसी परियोजना में हुई अभूतपूर्व प्रगति को दर्शाता है।** मार्च 2017 तक 2600 किमी (92%) के लिए सिविल कांट्रैक्ट और 2315 किमी (82%) के लिए इलेक्ट्रिकल व S & T कांट्रैक्ट अवार्ड किए जा चुके हैं।

इस वित्तीय वर्ष में 1504 किमी लंबी पश्चिमी डीएफसी के सभी कांट्रैक्ट अवार्ड करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया। इस दौरान डीएफसी में पहली बार सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल एवं टेलीकॉम का एकीकृत कांट्रैक्ट अवार्ड किया गया। इसके अतिरिक्त पश्चिमी डीएफसी में दो अन्य कांट्रैक्ट वर्ष 2016–17 के दौरान अवार्ड किए गए। वहीं पूर्वी डीएफसी में वर्ष 2016–17 के दौरान सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल व टेलीकॉम के क्षेत्र में रु. 4263.6 करोड़ मूल्य के कांट्रैक्टों को अंतिम रूप दिया गया।

इस विशाल परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में भी डीएफसीसीआईएल ने अथक प्रयास किए हैं। **परिणामस्वरूप वर्ष 2016–17 तक कुल आवश्यक भूमि का लगभग 96% (पीपीपी हिस्से को छोड़कर) अधिग्रहण किया जा चुका है।**

(पश्चिमी डीएफसी में जयपुर के पास रेनवाल में निर्मित 1.1 किमी लंबा वायाडक्ट)

वित्तीय क्षेत्र में भी डीएफसीसीआईएल की प्रगति उत्साहजनक रही है। **डीएफसी में पहली बार एक वित्तीय वर्ष में रु.10,000 करोड़ की राशि पूंजीगत मदों में खर्च की गई है। इस प्रकार पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले में डीएफसी ने पूंजीगत व्ययों में 21% की वृद्धि दर्ज की है।** दोनों ही कोरीडोरों में (पीपीपी सेक्शन को छोड़कर) वित्त की व्यवस्था शत प्रतिशत पूरी की जा चुकी है।

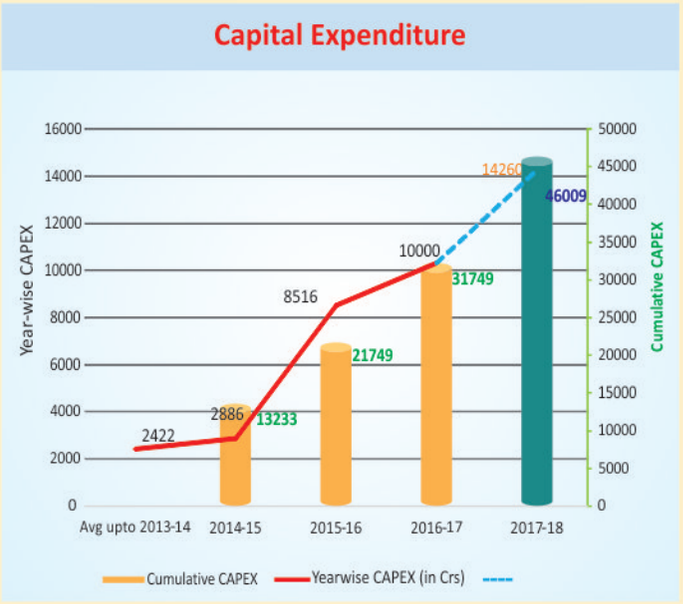

डीएफसी की इन उपलब्धियों का असर निर्माण कार्यों की प्रगति में साफ देखा जा सकता है। पूर्वी डीएफसी में 3.1 किमी लंबा सोन ब्रिज का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। वहीं पश्चिमी डीएफसी में रेनवाल वायाडक्ट का सिविल कार्य पूरा किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त दोनों कोरीडोरों में 100 से ज्यादा छोटे–बड़े पुलों का निर्माण 2016–17 के दौरान पूरा किया जा चुका है।

अत्याधुनिक एनटीसी मशीनों की मदद से दोनों ही कोरीडोरों में ट्रैक लिंकिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान, दोनों कोरीडोरों में कुल 373 किमी की मैकनाइज्ड ट्रैक लिंकिंग की गई। इस प्रकार दोनों कोरीडोरों में अब तक कुल मिलाकर 577 किमी की ट्रैक लिंकिंग की जा चुकी है। डीएफसी परियोजना के दूरगामी असर को दुनिया भर में पहचान मिल रही है। डीएफसीसीआईएल ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वर्ष 2016 का प्रतिष्ठित 'गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर सस्टैनबिलिटी' हासिल किया है।

डीएफसी के नए वित्त निदेशक ने पदभार संभाला

डीएफसीसीआईएल के नए निदेशक/वित्त श्री नरेश सालेचा ने 1 मार्च 2017 से पदभार संभाल लिया है। वर्तमान में, श्री सालेचा रेल मंत्रालय में सलाहकार (लेखांकन सुधार) तथा मिशन निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वे माननीय रेल मंत्री द्वारा बजट भाषण 2017–18 में उद्घोषित किए गए चार संकेंद्रित क्षेत्रों में से एक यानी– लेखांकन सुधार की देख–रेख कर रहे हैं। श्री सालेचा डीएफसीसीआईएल में निदेशक/वित्त का पदभार रेल मंत्रालय के अपने नियमित प्रभार के अतिरिक्त संभाल रहे हैं। उन्होंने डीएफसीसीआईएल के निवर्तमान निदेशक/वित्त श्री एम. के. मित्तल का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2017 को समाप्त हो गया।

रेलवे बोर्ड में वर्तमान पद से पहले श्री सालेचा, मंडल रेल प्रबंधक (DRM), अजमेर रह चुके हैं। उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय, आवास मंत्रालय तथा उत्तर–पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में बतौर संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार भी कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक, वित्त (वाणिज्य) भी सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने जहाजरानी महानिदेशालय, जहाजरानी मंत्रालय में बतौर वरिष्ठ महानिदेशक अंतरराष्ट्रीय संधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने, विश्व व्यापार संगठन (WTO), जिनेवा समझौते में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की तरफ से कई अन्य कार्यों को संपन्न किया है।

उनके पास कंपनियों में कार्य करने का विशाल अनुभव है और उन्होंने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में बतौर निदेशक कार्य किया है। इन उद्यमों में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (NBCC), आवास एवं शहरी विकास निगम (HUDCO), हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (HPL), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KMRCL), इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिजम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) तथा रेलटेल शामिल हैं। वे भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड में लगभग सात वर्षों तक मुख्य सतर्कता अधिकारी भी रह चुके हैं। श्री सालेचा की शैक्षणिक योग्यता बी.कॉम. (ऑनर्स), एमबीए तथा एलएलबी है।

वाइब्रेंट गुजरात प्रदर्शनी में डीएफसी की भागीदारी

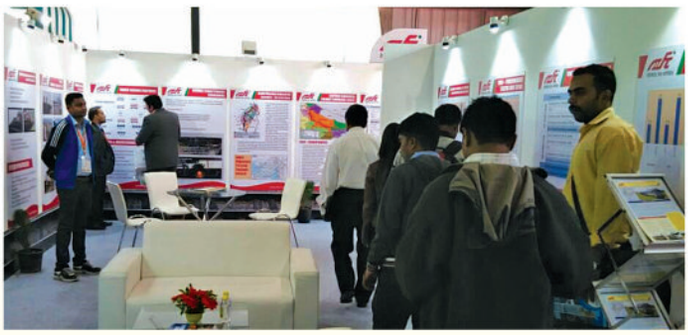

डीएफसीसीआईएल ने गांधीनगर में दिनांक 09 से 13 जनवरी 2017 तक आयोजित वाइब्रेंट गुजरात प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। प्रदर्शनी के दौरान डीएफसीसीआईएल के स्टाल पर बड़ी संख्या में दर्शकों ने भ्रमण किया और परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। डीएफसी के पश्चिमी कोरीडोर का एक बड़ा हिस्सा (565 किमी) गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजर रहा है। इसके अलावा डीएफसी गुजरात के पीपावाव, मुंद्रा और कांडला जैसे बंदरगाहों से आने वाले यातायात को भी देश के उत्तरी हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करेगा।

डीएफसीसीआईएल में राजभाषा गतिविधियां

- दिनांक 22.03.2017 को अक्टूबर–दिसंबर 2016 तिमाही अवधि की डीएफसीसीआईएल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री आदेश शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक महोदय की सहमति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:–
- राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाए। यह हमारी कानूनी बाध्यता है।
- SAP में हिंदी में कार्य करने की सुविधा को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
- सभी अधिकारी हिन्दी में मूल पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य को 100 प्रतिशत पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास करें।

हिंदी भाषा में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करते प्रबंध निदेशक श्री आदेश शर्मा

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता करते प्रबंध निदेशक श्री आदेश शर्मा

- दैनिक प्रयोग में आने वाले हिंदी शब्दों एवं वाक्यों की मुद्रित सूची अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए।
- कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा जारी किए जा रहे सभी पत्रों/कार्यालय आदेशों/परिपत्रों आदि की एक प्रति राजभाषा अनुभाग को ई–मेल से भेजी जाए।
- हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से एक को प्रत्येक तिमाही बैठक के दौरान पुरस्कृत किया जाए।
- राजभाषा अनुभाग को तिमाही रिपोर्ट समय से भेजी जाए तथा समय–समय पर उनकी वस्तुस्थिति की जांच भी की जाए।
- सभी अधिकारियों के दौरा कार्यक्रम एवं यात्रा भत्ता बिल केवल हिंदी में बनाए जाएं।

वर्ष 2016–17 की मुख्य उपलब्धियां

कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड

पश्चिमी डीएफसी

- **पश्चिमी डीएफसी के सभी सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल व टेलीकॉम कांट्रैक्ट अवार्ड**

वर्ष 2016–17 के दौरान रु.7379 करोड़ की लागत के निम्नलिखित कांट्रैक्ट अवार्ड किए गए:

- रेवाड़ी–दादरी सेक्शन के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल व टेलीकॉम के एकीकृत कांट्रैक्ट हस्ताक्षर। कांट्रैक्ट की लागत रु. 3799 करोड़
- वैतरणा–जेएनपीटी सेक्शन के लिए सिविल एवं ट्रैक पैकेज कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर। कांट्रैक्ट की लागत रु. 2949 करोड़
- मकरपुरा–जेनएनपीटी सेक्शन के लिए सिग्नल एवं टेलीकॉम पैकेज कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर। कांट्रैक्ट की लागत रु. 631 करोड़

पूर्वी डीएफसी

वर्ष 2016–17 के दौरान रु. 4263.6 करोड़ की लागत के निम्नलिखित सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल व टेलीकॉम कांट्रैक्ट अवार्ड किए गए:

- सोननगर जंक्शन के सिविल कार्यों के लिए कांट्रैक्ट, लागत रु. 365 करोड़
- मुगलसराय–भाऊपुर सेक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल कांट्रैक्ट, लागत रु. 847 करोड़
- साहनेवाल–पिलखानी सेक्शन के लिए सिविल कांट्रैक्ट, लागत रु. 1769.4 करोड़
- खुर्जा–दादरी सेक्शन के लिए सिविल कांट्रैक्ट, लागत रु. 511.3 करोड़
- भाऊपुर–मुगलसराय सेक्शन के लिए टेलीकॉम कांट्रैक्ट, लागत रु. 471 करोड़
- पिलखानी–साहनेवाल सेक्शन के लिए पीएमसी कांट्रैक्ट लागत रु. 68 करोड़
- खुर्जा–दादरी सेक्शन के लिए पीएमसी कांट्रैक्ट, लागत रु. 35 करोड़
- खुर्जा–दादरी एवं पिलखानी–साहनेवाल सेक्शनों के लिए QSAC कांट्रैक्ट
- देहरी ऑन सोन–सोननगर जंक्शन तथा दुर्गावती–मुगलसराय सेक्शनों में ट्रैक कार्यों के लिए कांट्रैक्ट लागत रु. 196.9 करोड़
- पूर्वी डीएफसी–3 (फेज 1) के लॉट 301 एवं 302 के लिए SESMRC कांट्रैक्ट

- खुर्जा–पिलखानी सेक्शन (सीपी–303) में सीएसटी कार्यों के लिए प्रथम चरण टेक्निकल प्रस्ताव की तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की क्लियरेंस के लिए जमा।
- खुर्जा–दादरी, पिलखानी–साहनेवाल, खुर्जा–पिलखानी सेक्शनों में सिस्टम कार्यों के लिए PQ मूल्यांकन रिपोर्ट पर वर्ल्ड बैंक की क्लियरेंस प्राप्त।
- खुर्जा–पिलखानी पीएमसी सेवाओं के लिए चयनित कंसल्टेंट के साथ कांट्रैक्ट
- पूर्वी डीएफसी–2 में सिग्नलिंग कार्य के लिए ISA की नियुक्ति (engagement) मामले में चयनित सूची मूल्यांकन रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की क्लियरेंस के लिए जमा।
- भारतीय रेल में, रेलवे प्लैनिंग ऐंड इनवेस्टमेंट ऑर्गनाइजेशन (RPIO) तथा स्पेशल यूनिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च ऐंड अनैलिसिस (SUTRA) के लिए मेसर्स KPMG के साथ कांट्रैक्ट
- भाऊपुर–खुर्जा सेक्शन में सिग्नलिंग कार्य हेतु इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट (ISA) के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए कांट्रैक्ट
- स्पेशल इस्टैब्लिशमेंट फॉर स्ट्रटीजिक टेक्नॉलजी ऐंड होलिस्टिक एडवांसमेंट स्टडी फॉर इंडियन रेलवे (SHRESTHA) के लिए ऑस्ट्रेलिया की IRT Monash University के साथ कांट्रैक्ट
- डीएफसीसीआईएल में पहली ई–टेंडरिंग के जरिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऐंड ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति के लिए टेंडर खोले गए। RITES के साथ कांट्रैक्ट समझौता लागू

अवार्ड किए गए कार्यों की प्रगति

पश्चिमी डीएफसी

रेवाड़ी–इकबालगढ़ सेक्शन

- वर्ष 2016–17 के दौरान कुल संवितरण (disbursement) रु. 1511 करोड़
- एनटीसी मशीन द्वारा 222 किमी मेकेनाइज्ड ट्रेक लिंकिंग
- मैकेनाइज्ड ट्रैक लिंकिंग 222 किमी
- भगेगा के बाद PSC स्लीपर प्लांट मारवाड़ में चालू, दोनों स्लीपर प्लांटों से कुल लगभग 5.5 लाख स्लीपरों का उत्पादन
- 33 मेजर ब्रिज पूरे किए गए। इसमें 1.2 किमी लंबा रेनवाल वायाडक्ट शामिल है।
- 324 छोटे ब्रिज पूरे किए गए।
- डीएफसीसीआईएल में लेवल क्रॉसिंग क्लोजर के साथ RUBs की कमिशनिंग शुरु और अधिकतम 42 RUBs की शुरुआत।
- मार्च 2017 तक स्थितिः अर्थवर्क 75%, ब्लैंकेटिंग 44%, कंक्रीटिंग 65%, बैलास्ट आपूर्ति 38%, स्लीपर उत्पादन 32%, ट्रैक लिंकिंग 17.20% (243 किमी)
- कुल भौतिक प्रगति (physical progreSS) 52% (लगभग), कुल वित्तीय प्रगति 43% (लगभग)
- मास्ट फाउंडेशन का निर्माण व डिजाइन कार्य प्रगति पर, 576 OHE फाउंडेशनों का कार्य पूरा
- सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन पैकेज के दस्तावेजों के जमा कराने एवं डिजाइन के कार्य प्रगति पर

इकबालगढ़–मकरपुरा सेक्शन

- 80% सर्वे डेटा वेलिडेशन और 90% जिओटेक्निकल जांच कार्य पूरा, डिजाइन कार्य शुरु
- कांट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में रु. 498 करोड़ का भुगतान

पश्चिमी डीएफसी फेज II (EMP-16) में इलेक्ट्रिकल कार्यों की प्रगति

- कांट्रैक्टर को धन राशि जारी। ट्रैक्शन पॉवर सिमुलेशन कार्यान्वित
- बड़े उपकरणों की साइजिंग का कार्य पूरा, खरबाओ TSS पर भौतिक निर्माण कार्य तेजी से चालू, जिओटेक्निकल सर्वे पूरा

पूर्वी डीएफसी

भाऊपुर–खुर्जा सेक्शन

- सिविल कार्य तेजी से प्रगति पर, कुल वित्तीय प्रगति 568.69 करोड़
- 297 किमी H/2 लेवल तक फॉर्मेशन, 273 किमी H लेवल तक फॉर्मेशन और 230 किमी ब्लैंकेटिंग
- एनटीसी मशीन से 120 किमी ट्रैक लिंकिंग पूरी (अब तक कुल ट्रैक लिंकिंग 196 किमी)
- इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए कांट्रैक्टर को रु. 231.20 करोड़ का भुगतान
- ज्यादातर इरेक्शन वर्क शुरु किए गए और 183 मास्ट इरेक्शन का कार्य पूरा
- ट्रैक्शन पॉवर सिमुलेशन और बड़े उपकरणों की साइजिंग को अंतिम रूप प्रदान
- कैटनेरी और कांटैक्ट तारों के लिए ऑर्डर जारी और टाइप टेस्ट पूरा

- सिग्नल व टेलीकम्युनिकेशन कार्य के 9 ब्लॉक सेक्शनों के लिए SIP अनुमोदित
- S&T केबलों के दो किश्तों का Factory Acceptance Test पूरा और 340 किमी केबल साइट पर प्राप्त

भाऊपुर–मुगलसराय सेक्शन

- अलाइनमेंट डिजाइन का कार्य 95% पूरा
- माइनर ब्रिज डिजाइन 100% और मेजर ब्रिज डिजाइन 80% पूर्ण
- दो स्लीपर प्लांट (हर पैकेज के लिए एक) शुरु
- महत्वपूर्ण ब्रिजों, जैसे– टोंस और यमुना का डिजाइन वर्क पूरा, Inland Waterways Authority of India (IWAI) से जरूरी अनुमोदन के बाद कार्य शुरु, 80% से अधिक फाउंडेशनों पर कार्य प्रगति पर
- H लेवल तक का फॉर्मेशन 43 किमी तक तथा H2 लेवल तक का फॉर्मेशन 65 किमी तक पूरा

मुगलसराय–सोननगर सेक्शन

- डीएफसी सिस्टम के सबसे लंबे पुल– सोन ब्रिज (3060 मीटर) पर रु.111 करोड़ (कुल लागत का लगभग 40%) खर्च

RUB का निर्माण और लेवल क्रॉसिंग को हटाना

- WDFC में लेवल क्रॉसिंग के हटाए जाने और उनकी जगह पर RUB बनाने का कार्य शुरु, उत्तर पश्चिम रेलवे के 263 RUB के लिए 133 लेवल क्रॉसिंग इंसर्ट
- EDFC-1 में डीएफसीसीआईएल के हिस्से में कुल 62 में से 37 (48%) लेवल क्रॉसिंग प्रीकास्ट सेगमेंट बिछाया गए, भारतीय रेल का 10 लेवल क्रॉसिंगों पर अपने हिस्से का काम पूरा
- पूर्वी डीएफसी में कुल 78 RUB बॉक्स की कास्टिंग
- राज्य सरकारों के साथ निरंतर बातचीत के कारण ROB की लागत को 50:50 के अनुपात में बांटने की सहमति
- तीन विभिन्न राज्यों से 15 ROB और 25 RUB के लिए प्राप्त इस सहमति से रेल मंत्रालय को राजस्व की भारी बचत

भूमि अधिग्रहण

- वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 826 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण व रु. 1340 करोड़ के मुआवजे का भुगतान
- 31 मार्च 2017 तक भूमि अधिग्रहण की स्थिति :

कुल अधिग्रहित की गई भूमि – 10750 हेक्टेयर

कुल अधिग्रहित की गई भूमि का प्रतिशत– लगभग 96% (पीपीपी सेक्शन को छोड़कर), 91.4% पीपीपी सेक्शन को मिलाकर

- राज्य सरकारों में मुख्य सचिव स्तर की बातचीत के बाद पूर्वी डीएफसी में 15 पैचों (कुल लंबाई 20 किमी) का अधिग्रहण
- पश्चिमी डीएफसी में 170 पैचों, (कुल लंबाई 28.3 किमी) का अधिग्रहण
- भूमि से जुड़े 2539 आर्बिट्रेशन मामलों और 197 कोर्ट केसों का निपटारा
- अब तक कुल 6555 आर्बिट्रेशन मामलों और 939 कोर्ट केसों का निपटारा

पर्यावरणीय अनापत्तियां

- बिहार के गया जिले में गोमोह–सोननगर सेक्शन के लिए सितंबर 2016 में स्टेज–II फॉरेस्ट क्लियरेंस प्राप्त
- पूर्वी डीएफसी– 1 के अंतर्गत आने वाले ताज ट्रपीजीअम जोन (TTZ) में 493 पेड़ों को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी
- पूर्वी डीएफसी के Cumulative Impact Assessment (CIA) को अंतिम रूप
- 6.2095 हेक्टेयर भूमि के लिए मार्च 2017 में स्टेज–1 की फॉरेस्ट क्लियरेंस प्राप्त
- पूर्वी डीएफसी 1 और पूर्वी डीएफसी 2 के निर्माण स्थलों पर 17,500 वृक्षारोपण

वित्त

- वर्ष 2016–17 में रु. 10,000 करोड़ के पूंजीगत व्यय, वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए रु. 8516 करोड़ के व्यय से 21% ज्यादा
- पूर्वी डीएफसी–3 के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ 650 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर
- दोनों कोरीडोरों के लिए वित्त की व्यवस्था पूरी
- क्रिसिल द्वारा "CCR AAA" और ICRA द्वारा [ICRA]AAA की रेटिंग बरकरार
- इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च द्वारा दीर्घकालीन IND AAA रेटिंग

मानव संसाधन

- ओपन मार्केट से 87 अभ्यर्थियों की भर्ती (08 सहायक प्रबंधक, 52 कार्यकारी और 27 कनिष्ठ कार्यकारी)
- विभिन्न स्थानों पर कुल 26 वित्त अधिकारी / कनिष्ठ वित्त अधिकारी और 17 वर्क इंजीनियरों की भर्ती
- 62 अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति (deputation) पर डीएफसीसी ज्वाइन किया, 11 अधिकारियों द्वारा स्थायी रूप से नियुक्ति (Permanent Absorption) ग्रहण
- विभिन्न स्तरों एवं विभागों के 50 अधिकारी / कर्मचारी पदोन्नत
- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 413 अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा हिस्सेदारी
- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के अंतर्गत 10 क्षेत्र इकाइयों में कुल 696 अभ्यर्थियों का विभिन्न रोजगार परक क्षेत्रों में प्रशिक्षण पूर्ण, 749 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण जारी
- इस वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे स्टेशनों पर फिल्टर्ड वाटर कूलर की व्यवस्था और पृथक (segregated) कूड़ेदानों की आपूर्ति CSR गतिविधि के रूप में शुरु, इसके लिए रु. 22.75 लाख की राशि आबंटित
- भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से कर्मचारी समूह बीमा योजना शुरु
- कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नई नीति स्वीकृत, कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु पर रु. 5 लाख और प्राकृतिक मृत्यु पर रु. 1 लाख के अनुदान की व्यवस्था, अंतिम संस्कार के लिए रु. 10,000 का अतिरिक्त अनुदान

भविष्य के कोरीडोर

- पूर्व तट कोरीडोर के लिए अंतिम PETS रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को दिनांक 04.04.2016 को जमा की गई।
- दक्षिणी कोरीडोर के लिए अंतिम PETS रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को दिनांक 10.03.2017 को जमा की गई।
- रेलवे बोर्ड द्वारा तीन कोरीडोरों के लिए PETS रिपोर्ट स्वीकृत:

उत्तर–दक्षिण कोरीडोर
पूर्व–पश्चिम कोरीडोर
पूर्व–तट कोरीडोर

व्यवसाय विकास

- डीएफसीसीआईएल की पोर्ट टर्मिनल रेल कनेक्टिविटी नीति और प्राइवेट साइडिंग रेल कनेक्टिविटी नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित
- हैवी हॉल रेल कपैसिटी डिवेलपमेंट इन इंडिया (HHRCDI) स्टडी पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट अनुमोदित
- डीएफसीसीआईएल और इसके कैचमेंट क्षेत्रों के लिए मार्केटिंग और व्यवसायिक नीतियों की सब्जेक्ट रिपोर्ट जमा

- डीएफसीसीआईएल के अविभेदकारी (non-discriminatory) एक्सेस के लिए कंसल्टेंसी सेवाओं पर अंतिम रिपोर्ट का ड्राफ्ट अनुमोदित, अंतिम रूप दिए जाने से पहले रेलवे बोर्ड से अंतिम टिप्पणियों की प्रतीक्षा
- ट्रैक एक्सेस चार्ज रिपोर्ट पूरी एवं प्रेषित

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस

- दो प्रेस कांफ्रेंसों का आयोजन, प्रमुख समाचार पत्रों और समाचार चैनलों द्वारा कवरेज
- दो ऑडियो–विडियो फिल्मों का निर्माण
- 19 प्रेस विज्ञप्तियां जारी, अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी में भी प्रेस विज्ञप्तियां जारी
- अनेक राष्ट्रीय समाचार पत्रों के लिए प्रबंध निदेशक का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आयोजित
- एनडीटीवी, ई–टी नाऊ और दूरदर्शन पर डीएफसीसीआईएल की विशेष कवरेज
- परियोजना की प्रगति पर त्रैमासिक पत्रिका– डीएफसी समाचार के चार अंकों का प्रकाशन
- ब्रिक्स एवं वाइब्रेंट गुजरात प्रदर्शनियों में भागीदारी

विविध

- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कॉर्पोरेट एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 16.05.2016 से 31.05.2016 तक स्वच्छता पखवाड़ा एवं दिनांक 28.05.2016 को स्वच्छता अभियान का आयोजन
- दिनांक 26.05.2016 से 01.06.2016 तक रेल हमसफर सप्ताह का आयोजन। प्रबंध निदेशक एवं निदेशक–गणों द्वारा वृक्षारोपण
- 21.06.2016 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास सत्र का आयोजन

सोशल मीडिया पर डीएफसी

फेसबुक पेज
फॉलोअर्स की संख्या 2500+
कुल पोस्टों की संख्या 100+
अपलोड किए गए फोटोग्राफ और विडियो 200+

ट्विटर हैंडल
फॉलोअर्स की संख्या 1500+
ट्वीट और रिप्लाई की संख्या 350+
अपलोड किए गए फोटोग्राफ और विडियो 100+

यू-ट्यूब-चैनल
सब्सक्राइबर्स की संख्या 800+
अपलोड किए गए विडियो 08
कुल Views की संख्या 1,40,000+

विदाई समारोह

श्री रजनीकांत ओझा, प्रबंधक/व्यवसाय विकास, कॉर्पोरेट कार्यालय दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर आयोजित समारोह में प्रबंध निदेशक श्री आदेश शर्मा ने उन्हें सप्रेम विदाई एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान कीं।

माह के उत्कृष्ट कर्मचारी

जनवरी 2017

श्री एन. के. मिश्र
परियोजना प्रबंधक/ इंजीनियरिंग/इलाहाबाद पूर्व

फरवरी 2017

श्री एम. एम. रत्नू
सहायक परियोजना प्रबंधक/ सिविल/अजमेर

मार्च 2017

श्री मनदीप सिंह
कार्यकारी/सिविल/लुधियाना

कार्य की प्रगति

पूर्वी डीएफसी के अलीगढ़ में संपन्न टर्फिंग का कार्य

पश्चिमी डीएफसी के ब्रिज संख्या 831 पर सब स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर

पूर्वी डीएफसी के इलाहाबाद में यमुना नदी पर बन रहा पुल

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित। कृपया पत्र–व्यवहार इस पते पर करें: संपादक, डीएफसी समाचार, पंचम तल, प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन भवन परिसर, नई दिल्ली– 110001, फैक्स 91-112345827, ईमेल: jkjain@dfcc.co.in, rkhare@dfcc.co.in
वेबसाइट: www.dfccil.gov.in **संपादक:** जे.के. जैन, **सह-संपादक:** राजेश खरे
www.facebook.com/dfccil.india www.twitter.com/dfccil_india www.youtube.com/dfccilindia